(a) At present, Antyodaya Programme is being implemented only in Himachal Pradesh where it was launched during 1990-91. Under this programme, the identified non-SC/ST families are provided subsidy at par with the SC/ST families under Integrated Rural Development Programme (IRDP). In addition, all identified Antyodaya families are given interest subsidy under the IRDP.

Under IRDP guidelines also, Antyodaya Approach i.e. assisting the poorest of the poor on priority basis is prescribed in respect of all the States/UTs. These guidelines are generally being followed.

(b) Requisite information about the State-wise targets and achievements of Afforestation and Tree Planting Activities during the Seventh Five Year Plan, 1990-91 and 1991-92 is given in Annexure. [*See* Appendix CLXII, Annexure No. 67].

(c) Afforestation and Tree Planting Activities are in pursuance of Central Policy.

(d) Information about Central Aid given to various States for Afforestation, Activities during Seventh Five Year Plan, Annual Plan 1990-91 and Annual Plan 1991-92 is given in Annexure. [*See* Appendix CLXII, Annexure No. 68]

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम

3303. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार आगामी वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों हेतु राज्य के लिए प्रति व्यक्ति आय तथा व्यय के लक्ष्यों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इन वर्षों के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर किया गया है । यह वर्ष 1992–93 पर भी लागू होता है ।

केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजना के तहत संसाधनों के हस्तांतरण के जरिए राज्य सरकार की उनके विकास कार्यक्रमों और कार्यकलापों की वित्त व्यवस्था में सहायता करती है ।

Schemes to help poor weavers

3304. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1776 given in the Rajya Sabha on 9th March, 1992 and state the details of the two schemes announced some months ago for upliftment of poor handloom weavers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): A statement is attached.

Statement

1. *Integrated Handloom Villages Development*:

This scheme proposes to adopt villages which are known for excellent craftsmanship in weaving but lack in infrastructure related to and not related to handlooms. About 24 villages are proposed to be taken up during 1991-92. Upto Rs. 25.00 lakhs will be provided from handloom budget to taken care of equity of the primary society, training, modernisation of

looms, common facility centre, housing-cum-workshed and general infrastructure like roads, cross-drainage, community halls, village electrification, primary school building, drinking water supply, health care centres for human beings and animals, marketing centres etc., provided local agencies bring in matching contribution of about Rs. 15.00 lakhs.

2. *Margin Money for Destitute Weavers:*

This scheme is meant for handloom weavers living below poverty line. The scheme envisages formation of co-operative societies and provision of margin money @ Rs. 2,000 per destitute member subject to a ceiling of Rs. 1.00 lakh per society. The weavers would also be provided training from the Weavers Service Centres. The society shall arrange for supply of assets and will also take the responsibility of marketing. Where it is not possible to form cooperative societies, weavers' associations may be formed, particularly if voluntary agencies are available. Existing schemes for handloom weavers like Welfare Schemes, Workshed-cum-Housing Scheme shall be dovetailed by the State Government.

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एन. टी. सी. मिलों का आधुनिकीकरण

3305. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित कपड़ा मिलों की संख्या क्या है और उनमें से घाटे पर चल रही तथा साथ ही लाभ कमा रही मिलों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कतिपय मिलों का आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है साथ ही उस पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एन टी सी के अधीन 124 मिलें (109 मिलें राष्ट्रीयकृत तथा 15 मिलें प्रबंधित) हैं । दो राष्ट्रीयकृत एककों को अभी पुन: चलाया नहीं गया है । इस प्रकार 122 मिलों में उत्पादन हो रहा है । वर्ष 1990–91 के दौरान 40 मिलों से नगदी घाटे उठाए थे ।

(ख) जी हां । राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने वर्ष 1992–97 की अवधि के लिए 532,78 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से एक निगमित योजना का प्रस्ताव किया है ।

(ग) आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए यह बताना संभव नहीं होगा कि कितनी मिलों को आधुनिकीकृत बना दिया गया है । फिर भी अब तक वित्तीय संस्थानों ने 135.41 करोड़ रु० के कुल परिव्यय से विभिन्न मिलों की 29 योजनाओं का अनुमोदन किया है तथा ये योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । इसमें सातवीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत 53.66 करोड़ रु० का परिव्यय भी शामिल है ।

Crisis faced by a subsidiary of NTC

3306. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether a letter dated 24th February, 1992 has been received from National Textile Corporation Employees' Union, Calcutta regarding the crisis facing National Textile Corporation (WBABO) Limited, a Subsidiary under National Textile Corporation Limited;

(b) if so, what are the reasons for the crisis; and

(c) what steps have been taken to defuse the crisis?